

वेतन संशोधन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

बीएसएनएल के नॉन एक्ज़िक्यूटिव कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन समझौते पर 08.10.2025 को आयोजित वेतन संशोधन समिति की बैठक में हस्ताक्षर किए गए हैं। BSNLEU के अखिल भारतीय केंद्र ने वेतन संशोधन समझौते की मुख्य विशेषताओं के बारे में कर्मचारियों को समझाने के लिए 13 से 18 अक्टूबर, 2025 तक सभी जिलों में विशेष बैठकें आयोजित करने का आह्वान किया है। इसलिए, यह नोट सभी सर्कल और जिला यूनियनों को भेजा जा रहा है ताकि हमारे नेता विस्तृत जानकारी दे सकें।

पृष्ठभूमि :

बीएसएनएल के नॉन एक्ज़िक्यूटिव कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तीसरी वेतन संशोधन समिति (तीसरी पीआरसी) की सिफारिश के अनुसार, घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारी वेतन संशोधन के हकदार नहीं हैं। तीसरी पीआरसी की यह सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही स्वीकार की जा चुकी है। यह सभी जानते हैं कि बीएसएनएल वर्ष 2009 से लगातार घाटे में चल रही है। इसलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, बीएसएनएल कर्मचारी वेतन संशोधन के हकदार नहीं हैं। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि घाटे में चल रहे किसी अन्य पीएसयू में वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

बीएसएनएल की यूनियनों और एसोसिएशनों ने, एयूएबी के बैनर तले, वेतन संशोधन के समाधान हेतु कई हड़तालें और अन्य संघर्षों के साथ-साथ सशक्त अभियान भी चलाए हैं। BSNLEU ने इन सभी संघर्षों और अभियानों में अग्रणी भूमिका निभाई है। BSNLEU ने वेतन संशोधन के समाधान की मांग को लेकर स्वतंत्र रूप से भी कई हड़तालें आयोजित की हैं।

वीरतापूर्ण हड़ताल/ कार्रवाई :

बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन की मांग को लेकर पहली हड़ताल 27.07.2017 को आयोजित की गई थी। एनएफटीई ने इस हड़ताल में भाग नहीं लिया था। इसके बाद, अक्टूबर 2017 में एयूएबी का गठन किया गया। इसके तुरंत बाद, एयूएबी ने बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन की मांग को लेकर 12 और 13 दिसंबर 2017 को दो दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया। एयूएबी ने दो "संचार भवन तक मार्च" कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया।

एयूएबी के आह्वान पर, अधिकांश सांसदों और कई केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन के मुद्दे पर समाधान का आग्रह किया गया। कोई सुधार न होने पर, एयूएबी ने 3 दिसंबर, 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया। तत्कालीन माननीय संचार राज्य मंत्री, श्री मनोज सिन्हा ने 3 दिसंबर, 2018 को एयूएबी नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर, 3 दिसंबर, 2018 से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी गई।

माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों पर अमल न होने के कारण, एयूएबी ने 18, 19 और 20 फरवरी, 2019 को तीन दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया। एयूएबी के बैनर तले, नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर दो विशाल धरने भी आयोजित किए गए, जिनमें देश भर से हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि 2021 में जंतर-मंतर पर धरना आयोजित करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने BSNLEU के तत्कालीन मुख्य सचिव साथी पी. अभिमन्यु और एनएफटीई के महासचिव साथी चंदेश्वर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला अभी भी पटियाला हाउस कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है।

संयुक्त हड़तालों के अलावा, BSNLEU ने बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन के निपटारे की मांग को लेकर कई हड़तालों आयोजित की हैं। 16 फरवरी, 2024 और 9 जुलाई, 2025 को BSNLEU द्वारा आयोजित हड़तालों में वेतन संशोधन का निपटारा पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग थी। उपरोक्त संघर्षों के अलावा, BSNLEU, एआईबीडीपीए और बीएसएनएलसीसीडीब्ल्यूएफ की समन्वय समिति ने भी बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन के निपटारे की मांग को लेकर कई आंदोलन और अभियान आयोजित किए हैं।

यहाँ यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि बीएसएनएल में लगातार हो रही हड़तालों और अन्य संघर्षों के कारण, तत्कालीन माननीय संचार राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने दूरसंचार विभाग को बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर नॉन एक्ज़िक्यूटिव कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया था। तदुसार, दूरसंचार विभाग ने

27.04.2018 को बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा। इस पत्र के आधार पर, नॉन एक्जिक्यूटिव कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु एक संयुक्त समिति का गठन किया गया।

वेतन संशोधन समिति में 2018 में ही नए वेतनमानों पर सहमति बन गई थी। हालाँकि, उसके बाद, बीएसएनएल प्रबंधन अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट गया और कम वेतनमान की पेशकश की। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रबंधन ने कड़ा रुख अपनाया कि नॉन एक्जिक्यूटिव कर्मचारियों को केवल 0% फिटमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रबंधन ने भत्तों में संशोधन को भी अस्वीकार कर दिया।

मान्यता प्राप्त यूनियनों ने अल्प वेतनमान, 0% फिटमेंट और भत्तों में संशोधन से इनकार को स्वीकार नहीं किया। उचित वेतन संशोधन के लिए संघर्ष और अन्य आंदोलन जारी रहे।

इन परिस्थितियों में, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि BSNLEU और एनएफटीई दोनों की मान्यता अवधि 16.10.2025 को समाप्त हो रही है, वेतन संशोधन समझौते पर 08 अक्टूबर, 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे।

निम्नलिखित मौजूदा और संशोधित वेतनमान हैं :

नये वेतनमान. (TABLE)

निस्संदेह, वेतनमान कम हैं। मान्यता प्राप्त यूनियनों, विशेष रूप से BSNLEU द्वारा किए गए सभी लंबे प्रयास सफल नहीं हुए। अंतिम प्रयास के रूप में, मान्यता प्राप्त यूनियनों ने कम से कम 4 वेतनमानों, अर्थात्, एनई-3, एनई-8, एनई-9 और एनई-10 में संशोधन की मांग की। हालाँकि, प्रबंधन ने इस मांग को भी स्वीकार नहीं किया। किसी भी वेतनमान में संशोधन पर विचार न करने के लिए प्रबंधन द्वारा दिया गया कारण यह है कि, उन्होंने पेंशन संशोधन के संबंध में, नॉन एक्जिक्यूटिव कर्मचारियों के प्रस्तावित नए वेतनमानों के बारे में दूरसंचार विभाग को पहले ही सूचित कर दिया था। इसलिए, बीएसएनएल प्रबंधन ने यह मजबूत रुख अपनाया है कि, किसी भी वेतनमान में संशोधन संभव नहीं है। साथ ही, यह उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है कि, कर्मचारियों को छोटे वेतनमानों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए दो महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

(a) समझौते में लिखित आश्वासन दिया गया है कि इस वेतन संशोधन में लागू किए गए अल्प वेतनमान, 01.01.2027 से लागू होने वाले अगले वेतन संशोधन में वेतनमान संशोधन का आधार नहीं बनेंगे।

(b) वेतन हानि से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। यदि किसी कर्मचारी को वेतन हानि होती है, तो उसे व्यक्तिगत वेतन देकर उसकी भरपाई की जाएगी, जिसे भविष्य में होने वाली वेतन वृद्धि में समाहित कर लिया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण समझौता है, क्योंकि 01.01.2007 से लागू वेतन संशोधन समझौते में भी वेतन हानि से सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। परिणामस्वरूप, कर्मचारियों के एक वर्ग को वेतन हानि का सामना करना पड़ा। BSNLEU उन जेई को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने में सफल रहा, जिन्हें वेतन हानि हुई थी। हालाँकि, अन्य संवर्गों के लिए, वेतन हानि की भरपाई के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने की हमारी माँग को बीएसएनएल बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया। तुलनात्मक रूप से, इस वेतन संशोधन समझौते में एक ठोस प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वेतन हानि की भरपाई व्यक्तिगत वेतन देकर की जाएगी।

फिटमेंट :

बीएसएनएल प्रबंधन लगातार मान्यता प्राप्त यूनियनों पर 0% फिटमेंट स्वीकार करने का दबाव बना रहा है। लेकिन, दोनों मान्यता प्राप्त यूनियनों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कम से कम 5% फिटमेंट दिया जाना चाहिए। 08.10.2025 को हस्ताक्षरित वेतन संशोधन समझौते में कहा गया है कि नॉन एक्जिक्यूटिव कर्मचारियों के लिए फिटमेंट, एक्जिक्यूटिव्स को दिए जाने वाले फिटमेंट के बराबर होगा। यह सभी जानते हैं कि 2018 में ही बीएसएनएल बोर्ड ने कार्यपालकों के लिए 15% फिटमेंट की सिफ़ारिश की थी। 0% लागू करना नॉन एक्जिक्यूटिव्स पर फिटमेंट की असमानता को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया है। निस्संदेह, यह एक उपलब्धि है कि, एक्जिक्यूटिव्स के साथ फिटमेंट की समानता सुनिश्चित की गई है।

भत्तों और सुविधाओं में संशोधन :

नवंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक, प्रबंधन कहता रहा है कि नॉन एक्जिक्यूटिव कर्मचारियों को भत्तों में संशोधन नहीं मिलेगा। इस मुद्दे पर भी एक बड़ा सुधार हुआ है। BSNLEU के दबाव के कारण, प्रबंधन ने भत्तों में संशोधन के लिए एक समिति का गठन कर दिया है।

वेतन संशोधन समझौते में उल्लेख किया गया है कि भत्तों में संशोधन, वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा। अब, यूनियनों और एसोसिएशन निश्चित रूप से बीएसएनएल प्रबंधन पर दबाव डालकर भत्तों में एक उचित संशोधन करवा सकते हैं, जिसे वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि से लागू किया जाएगा।

एचआरए का संशोधन :

एचआरए में संशोधन पर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि एचआरए में संशोधन को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया गया है। वेतन संशोधन समझौते में उल्लेख किया गया है कि एचआरए संशोधन पर बीएसएनएल बोर्ड विचार करेगा। यूनियनों और एसोसिएशनों के पास इस मुद्दे को प्रबंधन के समक्ष आगे बढ़ाने और इसे सुलझाने की गुंजाइश है।

विसंगतियाँ और विपथन :

जहां तक विसंगतियों और विचलनों का संबंध है, समझौते में कहा गया है कि उनका समुचित ढंग से समाधान किया जाएगा।

एनई-9 वेतनमान :

BSNLEU ने नॉन एक्जिक्यूटिव्स के लिए उचित वेतनमान प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, जिसमें जेई संवर्ग के लिए निर्धारित एनई-9 वेतनमान भी शामिल है। हालाँकि, प्रबंधन अडिग रहा और नवंबर, 2022 में प्रस्तावित किसी भी वेतनमान में संशोधन करने पर सहमत नहीं हुआ। हालाँकि, एसएनएटीटीए नेतृत्व एनई-9 वेतनमान के मामले में BSNLEU को बलि का बकरा बना रहा है। सीएचक्यू ने इस मुद्दे पर एक विस्तृत नोट प्रसारित किया है। यह नोट इसके साथ संलग्न है। साथियों से अनुरोध है कि वे इसे प्रत्येक जेई साथी को समझाएँ।

हमारे दिग्गजों को हार्दिक धन्यवाद :

जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है, BSNLEU ने सामूहिक और स्वतंत्र रूप से कई हड़तालें और अन्य आंदोलन आयोजित किए हैं। इन सभी संघर्षों और आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले बड़ी संख्या में साथी और नेता अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। निश्चित रूप से, इस वेतन संशोधन के समाधान में उनके त्याग और समर्पण का बहुत बड़ा योगदान है। इस अवसर पर, BSNLEU उन सभी साथियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है।

निष्कर्ष :

बीएसएनएल पिछले 16 वर्षों से घाटे में चल रही है। किसी भी अन्य घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने यह दृढ़ निर्णय लिया है कि घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों को वेतन संशोधन नहीं मिलेगा। यह समझना जरूरी है कि बीएसएनएल में यह वेतन संशोधन समझौता उपरोक्त प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए किया गया है। बीएसएनएल की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद, एक संतोषजनक वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बीएसएनएल निदेशक मंडल की स्वीकृति के बाद, यह वेतन संशोधन समझौता दूरसंचार विभाग के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

हालाँकि, वेतन संशोधन को मंजूरी देने से पहले, दूरसंचार विभाग को बीएसएनएल के लिए तीसरे वेतन आयोग के वहनीयता खंड से केंद्रीय मंत्रिमंडल की छूट लेनी होगी। BSNLEU अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ मिलकर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की छूट और दूरसंचार विभाग की मंजूरी प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से शीघ्र कार्रवाई करेगा। सीएचक्यू अपने सीएचक्यू, सर्कल और जिला स्तर के पदाधिकारियों से इस वेतन संशोधन समझौते को पूरी जानकारी और सही परिप्रेक्ष्य में समझाने का आग्रह करता है।

- अनिमेष मित्रा, महासचिव, BSNLEU.